TIME LINE FOR ISSUANCE OF PROPERTY ID

748. SH. RAKESH DAULTABAD, MLA: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

a) the present status of implementation and issuance of property IDs in Sector 58 to 115 of Gurugram;

b) the sectorwise details of all societies/gated colonies where survey has been conducted or pending, total number of flats/ houses in each society, scope of survey, name of survey agency, date of survey and number of property IDs issued in each sector/ society and gated colony since implementation of mandatory registration of property IDs for transfer/ sale/ conveyance deed registration; and

c) whether any timeline has been fixed by the Government under "Right to Service" for issuance of property ID, within which the request must be processed by the department?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

a) The Sectors 58 to 115 falls under Municipal Corporation, Gurugram and Municipal Corporation, Manesar. Total Property IDs of these areas on No Dues Certificate (NDC) portal as on date are 1,22,711 i.e., 84,137 pertaining to Municipal Corporation, Gurugram and 38,574 of Municipal Corporation, Manesar. The data on NDC portal will be updated after the completion of property survey.

b) There are 345 Societies/Gated Colonies having 1,22,711 number of units on the NDC portal which are used for registration purposes. The detailed list is attached as Annexure-'I'. The project for conducting the Property Tax survey for the municipalities falling in the State was allotted to M/s Yashi Consulting Services Pvt. Ltd. and the project agreements were signed on 13.09.2019. It is pertinent to mention here that most of the sectors between 58 to 115 falls either under the extended limit of Municipal Corporation, Gurugram (extended on 28.12.2020) or Municipal Corporation, Manesar (constituted on 24.12.2020) and the work order for these were given to M/s Yashi Consulting Services Pvt. Ltd. on 01.03.2021 and the work

was started after the work order. The scope of work includes door to door survey of all the properties within the Municipalities along with GIS tagging and putting the data in public domain. After receiving the objections and their settlement, re-assessment notices are to be distributed before finalizing the Property Tax against each unit.

c) Presently new property ID is being created through the NDC portal. The property ID is generally created within 10 working days from the date of receipt of the application. This matter regarding bringing it under the ambit of Right to Service Act, 2014 is under consideration of the Government by making the provision of this service under the said Act.

सम्पत्ति आई.डी. जारी करने के लिए समय सीमा

748. श्री राकेश दौलताबाद, एम.एल.ए. : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) गुरूग्राम के सैक्टर 58 से 115 में संपत्ति आई.डी. के क्रियान्वन तथा जारी करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन सभी सोसायटियों/गेटेड कॉलोनियों जंहा सर्वेक्षण किया गया है या लंबित है, का सैक्टर–वार ब्यौरा क्या है, प्रत्येक सोसायटी में फ्लैटों/घरों की कुल संख्या कितनी है, सर्वेक्षण का क्षेत्र, सर्वेक्षण एजेंसी का नाम, सर्वेक्षण की तिथि तथा हस्तांतरण/बिक्री/विलेख पंजीकरण के लिए संपत्ति आईडी के अनिवार्य पंजीकरण को क्रियान्वयन से अब जारी की सम्पति की आई.डी. का सैक्टर वार ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या सरकार द्वारा संपति आई.डी. जारी करने के लिए ''सेवा का अधिकार'' के तहत जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा अनुरोध को प्रक्रियाधीन किया जाना है, की कोई समय सीमा निष्चित की गई है?

डॉ0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

(क) सैक्टर 58 से सैक्टर 115 नगरनिगम गुरूग्राम तथा नगरनिगम मानेसर के अन्तर्गत आते है। नगरनिगम गुरूग्राम की 84,137 सम्पत्ति तथा मानेसर नगरनिगम की 38,574 सम्पत्ति अर्थात दोनों क्षेत्रों की कुल सम्पत्ति 1,22,711 सम्पत्तियों का विवरण एन.डी.सी. पोर्टल पर मौजूद है। सम्पत्ति सर्वेक्षणपूर्ण होने के उपरान्त एन0डी0सी0 पोर्टल पर डाटाअपडेट कर दिया जायेगा।

(ख) कुल 345 सोसायटियों/गेटेड कॉलोनियां जिनकी कुल 1,22,711 सम्पत्तियां एन0डी0सी0 पोर्टल पर दर्ज है जिनका उपयोग दस्तावेज पंजीकरण हेतू होता है, विस्तृत सूचीपताका ''क'' परसंलग्न है। राज्य की सभीनिकायों के सम्पत्ति सर्वेक्षण का कार्यमैसर्ज याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेटलिमिटेड को आंबटित किया गया है तथा परियोजना अनुबन्ध पर हस्ताक्षर दिनांक 13.09.2019 को किए गये थे। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि सैक्टर 58 से 115 का अधिक्तर क्षेत्र या तो नगरनिगम गुरूग्राम की दिनांक 28.12.2020 को हुई सीमावृद्धि का हिस्सा है या दिनांक 24.12.2020 को गठित हुई नगरनिग ममानेसर के अन्तर्गत आते हैं। इनके सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 01.03.2021 को मैसर्ज याशी कंसल्टिंग सर्विसेजप्राईवेट लिमिटेड को दिया गया था तथा इस कार्य आदेश के उपरान्त ही इसका कार्य आरम्भ हुआ। कार्य के दायरे में जी.आई.एस. टैगिंग और डाटा को सार्वजनिक डोमेन में डालने के साथ–साथ नगरनिकायों के अन्दर सभी सम्पत्तियों का घर–घर का सर्वेक्षण करना शामिल है। आपत्तियों की प्राप्ति एवं उनके समाधान के बाद, प्रत्येक इकाई के विरूद्ध सम्पत्ति कर को अन्तिम रूप देने से पूर्व पुनर्मूल्यांकन नोटिस वितरण किये जाने हैं।

(ग) वर्तमान में एन.डी.सी. पोर्टल के माध्यम से नई संपति आई.डी बनाई जा रही है। नई संपति आई.डी. आम–तौर पर आवेदन प्राप्त होने से 10 कार्य दिवसों के अन्दर–अन्दर बनाई जाती हैं। सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में इसे लाने हेतू मामला सरकार के विचाराधीन है।